

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक बीकानेर द्वितीय

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशन लाल पुत्र स्व० श्री रामलाल
 2. श्री नानू राम पुत्र स्व० श्री रामलाल
- निवासीगण ग्राम नापासर, तहसील व जिला बीकानेर

...अप्रार्थीगण

एकलपीठ .

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोरखणा

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री विकाश पाराशर

....प्रार्थी की ओर से

...अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.12.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी विभाग द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) बीकानेर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के निर्णय दिनांक 30.07.2014 प्रकरण संख्या 30/14 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को अस्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा एक पारिवारिक बटवारानामा आवासीय सम्पत्ति का दिनांक 09.06.2011 को पंजीयन वास्ते उप पंजीयक, बीकानेर द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे उप पंजीयक द्वारा दस हजार रुपये मुद्रांक शुल्क व सम्पत्ति की मालियत 8,44,176/- रुपये पर 1 प्रतिशत से मुद्रांक कर रुपये 8,450/- रुपये व अन्य शुल्क 9,600/- रुपये वसूलकर दस्तावेज बटवारानामा पंजीयन कर अप्रार्थीगण को लौटा दिया गया। तत्पश्चात् महालेखाकार निरीक्षक दल द्वारा उक्त बटवारानामा पर मुद्रांक अधिनियम की धारा 42 के अनुसार एक बड़े भू-भाग को छोड़कर शेष भाग पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक शुल्क नहीं लेने से 5,450/- रु. की कर अपवंचना से आक्षेपित किया गया। तत्पश्चात् उप पंजीयक द्वारा मुद्रांक वसूली वास्ते अप्रार्थीगण को मुद्रांक अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत राशि जमा कराने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उपपंजीयक द्वारा प्रकरण वसूली हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को मुद्रांक अधिनियम की धारा 51(3) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 व सपठित नियम 65(1) राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ने कलक्टर मुद्रांक के यहा जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा यह अवधारित किया है कि प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार अधिकतम

22/

लगातार.....2

10,000/- मुद्रांक कर व सम्पत्ति की मालियत 8,44,176/- रु. पर 1 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क 8,450/-रूपये व अन्य शुल्क 9,600/- वसूल किये गये हैं जो विधिसम्मत है तथा इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स खारिज किया है जिसके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 2 (XX) में विभाजन-पत्र (Partition Deed) को परिभाषित किया गया है। अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र पर सम्पत्ति के एक सबसे बड़े हिस्से को छोड़कर शेष अलग हुये हिस्से/हिस्सों पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है। प्रश्नगत दस्तावेज के द्वारा विभाजन-पत्र के माध्यम से अचल सम्पत्ति का विभिन्न बटवाराकर्ताओं के मध्य विभाजन किया गया है जिसमें सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा स्वामित्व एवं अधिकारी हस्तान्तरित हुआ है। अतः उक्त आर्टिकल-42 की अनुपालना करते हुये कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर प्रभार्य है जिसके आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 09.06.2011 को पैतृक सम्पत्ति का विभाजन प्रलेख निष्पादित हुआ था। यह सम्पत्ति अप्रार्थीगण को उनके पिता से प्राप्त हुई थी। दस्तावेज द्वारा पैतृक सम्पत्ति का बटवारा किया गया है जिस पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 के अनुसार अधिकतम मुद्रांक कर 10,000/- देय है। आन्तरिक लेखा जांच दल के द्वारा दस्तावेज की गलत व्याख्या करते हुए गलत अर्थ निकालते हुए जो मूल्यांकन किया गया, वह विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने निवेदन किया कि प्रार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

6. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के आर्टिकल-42 के अनुसार विभाजन पत्र के दस्तावेज में संपत्ति के एक बड़े हिस्से को छोड़ते हुये शेष हिस्से की मालियत पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होना चाहिए। अप्रार्थी ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारा नामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक

कर लिये जाने की रियायत होने की बात कही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स इस आधार पर खारिज किया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 संख्या एफ4(14)एफडी/डिवी/98-52 के अनुसार पैतृक संपत्ति के बंटवारानामा पर एक बड़े हिस्से को छोड़कर शेष हिस्सों की मालियत पर 1 प्रतिशत अधिकतम रु. 10,000/- मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नहीं तथा इसका लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 09.06.2011 पर देय है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :-

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable.

इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नहीं मानी जा सकती।

257

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक: एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :-

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :- "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प. 2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हैं। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क में रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 09.06.2011 पर देय है।

8. प्रकरण में इस बिन्दु पर भी विचार किया जाता है कि जिस संपत्ति का विभाजन पत्र निष्पादित किया गया था वह संपत्ति पैतृक है या नहीं। पैतृक संपत्ति के संबंध में The Advanced Law Lexicon (Law Dictionary compiled and edited by P. Ramanatha Aiyar Published by Wadhwa & Company Nagpur, India 3rd Edition Reprint 2007) में निम्न प्रकार उल्लेख किया गया है :- **Ancestral Property : If property came to a son as gift from his father, it can not be regarded his ancestral property. Ancestral properties in the ordinary sense mean property of the father which is inherited. Ancestral property does not necessarily mean property which has been a long time in a family, it rather means, property derived from the proprietor's father.**

इस डिक्शनरी में पैतृक संपत्ति के संबंध में की गई व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यदि कोई संपत्ति पिता या उच्चतर श्रेणी के पूर्वजों से कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति की श्रेणी में है।

254

बंटवारनामा दस्तावेज पंजीयन दिनांक 09.06.2011 में बंटवारनामा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हुआ है। दस्तावेज में श्री रामलाल का स्वर्गवास होना अंकित है तथा दस्तावेज में यह उल्लेख है कि दस्तावेज से संबंधित संपत्ति श्री रामलाल को उनके पिता लूणाराम के नाम दर्ज थी। इस प्रकार संपत्ति श्री रामलाल के पिता की संपत्ति है परन्तु अप्रार्थीगण को यह संपत्ति उनके पिता श्री रामलाल से विरासतन प्राप्त हुई है जो अप्रार्थीगण की पैतृक संपत्ति मानी जायेगी। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति पैतृक नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर बंटवारनामा से संबंधित संपत्ति अप्रार्थीगण को उनके पिता की संपत्ति विरासतन प्राप्त होने के कारण पैतृक एवं ऐसे दस्तावेज पर अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 लागू होने के कारण निगरानी सारहीन है एवं खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नैथूराम)
सदस्य